objective of growth including the growth of industry and investments. The decision to expand the list for automatic approval has accordingly been taken by Government to facilitate expeditious approval of proposals. Government have taken due care to ensure that the interests of the small scale sector are protected.

पिछड़े क्षेत्रों में विदेशी निवेश का उपयोग

950. श्री नागमणि: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत के पिछड़े क्षेत्रों में विदेशी निवेश का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण इन क्षेत्रों का संतुलित विकास नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है; इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) सरकार की नीति के अनुसार अनिवासी भारतीयों को भारत में कहीं भी निवेश करने की छूट है और इसके लिए परियोजना का स्थान निवेशक की पसंद पर निर्भर करता है।

(ग) जी, नहीं। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार विकास केन्द्र योजना, समन्वित आधारभूत संरचना विकास योजना और परिवहन राज सहायता योजना चला रही है।

बिहार में उद्योगों की स्थापना

951. श्री नागमणि: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में और विशेषकर बिहार में नये उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या ये सुविधाएं उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) भारतीय उद्योगों को गतिशील तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने घरेलू तथा विदेशी निवेश दोनों ही के अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये कई कदम उठाये है। 14 उद्योगों की एक छोटी सूची के अलावा जिनके लिये औद्योगिक अनुमोदन अपेक्षित है, सभी अन्य उद्योगों को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। हाल ही में 1997 के प्रेस नोट संख्या 2 द्वारा विदेशी इक्यूटी के लिये स्वत: अनुमोदनार्थ उद्योगों की सूची का विस्तार किया गया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वत: अनुमोदनार्थ 74 प्रतिशत विदेशी इक्यूटी तक के लिये कतिपय श्रेणियों को शामिल किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने विकास केन्द्र योजना तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिये परिवहन आर्थिक सहायता योजना भी आरंभ की है। भारत सरकार की अवसंरचना क्षेत्र में तथा विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों में निवेश हेतु करावकाश की योजना भी है। जहां तक बिहार में सुविधाओं का प्रश्न है औद्योगिक विकास प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों को उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है। भारत सरकार की विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत बिहार के लिये 6 विकास केन्द्र अनुमोदित किये गये है तथा आज तक उन्हें 750 लाख रु की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

(ख) और (ग) इन सुविधाओं की समय समय पर पुनरीक्षा की जाती है तथा जब कभी भी आवश्यक होता है नीतिगत परिवर्तन किये जाते है।

Slack in industrial growth rate

952. SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRI JANARDHANA POOJARY:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether growth in industrial production has continued to be slack so far in the current year;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps Government have taken/ propose to take to increase production?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) Yes, Sir. The deceleration in industrial growth has been due to constraints in infrastructure sectors, terms of credit availability, lower demand from export and other sectors etc. Sector specific strategies have been initiated to remove constraints in [illegible] for ir[illegible]ors. Corr[illegible]